



जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला

स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)



जन-जन के लिए सुलभ, त्वरित एवं किफायती न्याय

क्या है स्थायी लोक अदालत?

स्थायी लोक अदालत एक वैधानिक मंच है, जिसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-B के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सरल, शीघ्र एवं कम खर्च में समाधान उपलब्ध कराना है।

यह मंच विवादों को पहले आपसी समझौते (Conciliation) के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं निर्णय (Adjudication) भी प्रदान करता है।

स्थायी लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएँ

स्थायी लोक अदालत में न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया सरल एवं अनौपचारिक होती है, जिससे आम नागरिक बिना जटिल कानूनी प्रक्रिया के अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं। यह मंच विवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करता है तथा पक्षकारों को आपसी समझौते का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। यदि समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत स्वयं मामले का निर्णय कर सकती है। इसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

लोक उपयोगिता सेवाएँ (Public Utility Services)

स्थायी लोक अदालत उन विवादों की सुनवाई करती है जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित होते हैं। इनमें परिवहन सेवा, डाक सेवा, दूरसंचार सेवा, विद्युत सेवा, जलापूर्ति सेवा, सार्वजनिक स्वच्छता सेवा, अस्पताल एवं औषधालय सेवा तथा बीमा सेवा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की जा सकती है।

किन मामलों में आवेदन किया जा सकता है?

नागरिक विद्युत आपूर्ति एवं बिजली बिल से संबंधित विवाद, जलापूर्ति संबंधी शिकायतें, बीमा दावों से जुड़े विवाद, परिवहन सेवाओं से संबंधित समस्याएँ, डाक एवं दूरसंचार सेवाओं से संबंधित शिकायतें तथा अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान हेतु स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

किन मामलों की सुनवाई नहीं होती?

स्थायी लोक अदालत गैर-समझौतायोग्य (Non-Compoundable) अपराधों तथा गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले, जिनकी दावा राशि विधि द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो, भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली

1. प्रथम चरण- सुलह (Conciliation)

मामला प्राप्त होने पर स्थायी लोक अदालत सर्वप्रथम पक्षकारों के बीच आपसी समझौता कराने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विवाद का सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।

2. द्वितीय चरण - निर्णय (Adjudication)

यदि पक्षकारों के बीच समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत स्वयं मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय प्रदान करती है। यही विशेषता स्थायी लोक अदालत को सामान्य लोक अदालत से अलग बनाती है।

सामान्य लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत में अंतर

सामान्य लोक अदालत केवल समझौता कराने का प्रयास करती है। यदि समझौता नहीं हो पाता है तो मामला पुनः संबंधित न्यायालय में वापस चला जाता है। इसका आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता है। स्थायी लोक अदालत समझौते के साथ-साथ निर्णय भी दे सकती है। यदि समझौता नहीं हो पाता है तो यह स्वयं मामले का निस्तारण करती है। यह नियमित रूप से कार्यरत रहती है।

“ समझौते से समाधान- स्थायी लोक अदालत के साथ आसान न्याय ”

“ सुलह भी, निर्णय भी - स्थायी लोक अदालत सभी के लिए ”